

ए. सी. जे. न्यामूर्ति एम. एम. कुमार, और
न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल के समक्ष

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद,-याचिकाकर्ता
बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू पी. सं. 2007 का 6573

23 सितंबर, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14,19 (1) (छ) और 226-हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003-धारा 8-हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम-20 (1) और 20 (4)-विभिन्न व्यक्तियों से सामग्री की खरीद करने और उसी को बेचने और भुगतान किए गए कर को इनपुट टैक्स क्रेडिट की कटौती के बाद ट्रेजरी में जमा करने के व्यवसाय में लगी याचिकाकर्ता फर्म-मूल्यांकन प्राधिकरण ने पाया कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की कटौती करने का हकदार नहीं था, क्योंकि मूल्य वर्धित कर (वैट) डीलर जिनसे याचिकाकर्ता ने कुछ सामान खरीदा था, उन्होंने राज्य कोषागार में पूरा कर जमा नहीं किया था-अधिनियम की धारा 8 (3) और नियम 20 (1), 20 (4) को मनमाने और अनुचित होने के कारण चुनौती दी जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि प्रमाण पत्र और घोषणा की वास्तविकता की जांच प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है, लेकिन उसमें दर्ज किए गए बयानों की शुद्धता या सच्चाई स्थापित करने की जिम्मेदारी निर्धारिती पर नहीं डाली जा सकती है। अधिकारी इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या फॉर्म वैट-सी4 फर्जी था और व्यापारी द्वारा विक्रेता व्यापारी के साथ मिलीभगत में पंजीकृत विक्रेता व्यापारी द्वारा खरीदा गया था।

(पैरा 27)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि कर कि अदायगी न करने की जिमेवारी पंजीकृत व्यापारी खरीददार के ऊपर नहीं डाली जा सकती जब तक दोनों की मिलीभगत स्थापित न हो जाये।

(पैरा 33)

782

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(2)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 8 (3) के प्रावधान और नियम 20 के उप-नियम (1) और (4) अधिकांतीत नहीं कहे जा सकते, लेकिन वे ऊपर बताए गए तरीके से लागू होंगे।

(पैरा 34)

के. एल. गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप गोयल, अधिवक्ता के साथ
याचिकाकर्ता के लिए।

राजीव अग्निहोत्री और विजय पाल अधिवक्ता, 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. सं.
9633,10007,11712 और 11713 में याचिकाकर्ता के लिए।

अवनीश झिंगन, अधिवक्ता 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. सं.

14142,14150,14220,14224 और 14248 में याचिकाकर्ता के लिए

विनोद S.Bhardwaj, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा
प्रीतिवादीओ के लिए।

न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल।

(1) इस आदेश द्वारा छब्बीस रिट याचिकाओं का एक समूह, अर्थात्। सिविल रिट याचिका सं. 6573, 6888, 6913, 6932, 6933, 7015, 7031 और 2007 की 7107, 2008 की 9350 और 18345, 2009 की 4259 और 11581, 2010 की 2296, 2297, 3340, 8275 और 23400, 9633, 10007, 11712, 11713, 14142, 14150, 14220, 14224 और 2011 की 14248 का निपटारा किया जा रहा है क्योंकि इन सभी याचिकाओं में शामिल कानून के प्रश्न सामान्य हैं। इन याचिकाओं में उठाया गया

सामान्य मुद्दा निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट इस आधार पर न करने के कि जिन डीलरों से याचिकाकर्ताओं ने सामान खरीदा है, उन्होंने राज्य कोषागार में पूरा कर जमा नहीं किया के सम्बन्ध में है। याचिकाकर्ताओं को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') की धारा 8 के प्रावधानों के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट की कटौती का हकदार नहीं ठहराया गया है। तथ्यों को 2007 की सिविल रिट याचिका No.6573 से लिया गया है।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इन याचिकाओं में की गई प्रार्थना अधिनियम की धारा 8 (3) को इस आधार पर अधिकारातीत घोषित करने के लिए रिट जारी करने के लिए है कि यह नियम मनमाना और अनुचित है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है और राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है। आगे रिट में प्रार्थना कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 के नियम

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल)

783

20 (1) और 20 (4) को (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम') अनुचित और मनमाना घोषित करने के लिए की गई है क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 14 की कठोरता से प्रभावित हैं। याचिकाकर्ता ने आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण, सिरसा द्वारा पारित दिनांकित 15.3.2007, संलग्नक P5 आदेश को इस आधार पर रद्द करने के लिए सरशियोरेराई की प्रकृति में एक रिट की भी मांग की है कि यह असंवैधानिक है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी करके पारित किया गया है।

(3) विवाद को जानने के लिए आवश्यक तथ्य, जैसा कि याचिका में परिलक्षित होता है, यह है कि याचिकाकर्ता मेसर्स घेरू लाल बाल चंद के नाम के तहत एक साझेदारी फर्म है, जो कपास की बिक्री और खरीद के व्यवसाय में लगी हुई है। याचिकाकर्ता अलग-अलग व्यक्तियों से सामग्री खरीदता है और संबंधित अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में उसे बेचता है और इनपुट टैक्स

क्रेडिट की कटौती के बाद व्यापारी द्वारा भुगतान जाने वाले कर का भुगतान कोषागार में करता है। फर्म अधिनियम के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, 'बिक्री कर अधिनियम') के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता के अनुसार, अधिनियम के तहत योजना यह है कि वस्तुओं की बिक्री पर गणना किए गए कर को "उत्पादन कर" के रूप में माना जाएगा। लेकिन यदि खरीदारी हरियाणा राज्य के भीतर से की जाती है, तो ऐसी खरीद पर भुगतान किए गए कर को आउट-पुट देयता से अलग किया जाता है और परिणामी कर का भुगतान विक्रेता द्वारा किया जाता है। आकलन प्राधिकरण ने पाया कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट में कटौती करने का हकदार नहीं था, क्योंकि जिन मूल्य वर्धित कर (वैट) विक्रेताओं से याचिकाकर्ता ने कुछ सामान खरीदे थे, उन्होंने राज्य कोषागार में पूरा कर जमा नहीं किया था। हालांकि, विक्रेता का रुख यह है कि उसने अधिनियम के तहत मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा विधिवत पंजीकृत विक्रेताओं से वास्तविक खरीद की और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उन्होंने पूर्ण कर का भुगतान किया या नहीं, उसे आवश्यक इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त विक्रेताओं ने अपनी कर देनदारी का निर्वहन किया और उनके लिए उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट में कटौती करके उनके द्वारा देय कर जमा किया।

(4) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब कोई पंजीकृत विक्रेता बिक्री करता है और खरीद विक्रेता को अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कर चालान जारी करता है, तो बाद वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का हकदार होता है। इस प्रकार, खरीदारी करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि माल बेचने वाला विक्रेता एक पंजीकृत विक्रेता है और उसने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर चालान जारी किया है। अधिनियम की धारा 8 (3) के अधिदेश के अनुसार,

एक व्यापारी को बेचे गए माल के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे पर सवाल उठाया जा रहा है, खरीद व्यापारी को कार्यवाही का संचालन करने वाले प्राधिकरण

के समक्ष पेश करने के लिए कहा जा सकता है, जो विक्रेता द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र है। इस तरह के दावे की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब मूल्यांकन प्राधिकरण प्रमाण पत्र की सामग्री के बारे में संतुष्ट हो। यह भी दावा किया गया है कि बिक्री विक्रेताओं ने अपनी कर देनदारी का भी निर्वहन किया है और उन्हें उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट में कटौती करके देय कर को अपने हाथों में जमा कर दिया है। जब भी याचिकाकर्ता ने विक्रेताओं से खरीदारी की है, तो उसने आवश्यक वैट चालान प्राप्त किए हैं। नियमों के नियम 20 के संदर्भ में वैट सी-4 प्रपत्र भी याचिकाकर्ता द्वारा विक्रेताओं से प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त किए जाते हैं कि उन्होंने याचिकाकर्ता को की गई बिक्री पर अधिनियम के तहत कर की पूरी राशि का भुगतान किया है। याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा की गई बिक्री और खरीद को दर्शाते हुए विभिन्न अवधियों के लिए अपना विवरणी भी दाखिल किया। मूल्यवर्धन पर कर का भुगतान किया गया था और बिक्री विक्रेताओं द्वारा जारी चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है। यह भी दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा फॉर्म आर2 में वार्षिक विवरणी भी दाखिल की गई है, जिसमें 31.3.2004 पर समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उसके द्वारा की गई सभी बिक्री और खरीद का सारांश दिखाया गया है। 31.3.2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, याचिकाकर्ता के मामले को आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण, हिसार-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जांच के लिए लिया गया था। उस संबंध में, नियमों के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिकाकर्ता को नोटिस पी3/ए और पी3/बी इस आधार पर जारी किए गए थे कि इसने मेसर्स हंस राज राम कुमार, फतेहाबाद, मेसर्स मोहन लाल मनीष कुमार, फतेहाबाद, मेसर्स चंदूलाल मोहन लाल, फतेहाबाद, मेसर्स संत लाल हरबंस लाल, फतेहाबाद, मेसर्स सुरेश कुमार एंड कंपनी, फतेहाबाद, मेसर्स पार्टिक एंटरप्राइजेज, मेसर्स जगदीश राय जय भगवान, फतेहाबाद और मेसर्स महावीर प्रसाद रजत कुमार, फतेहाबाद से खरीद की थी, जिन्होंने कोषागार में कर जमा नहीं किया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव किया गया था। याचिकाकर्ता को क्रमशः 13.2.2007 और 6.3.2007 द्वारा कारण दिखाने का निर्देश दिया गया था। अपने जवाबों में, अन्य आधारों के अलावा, याचिकाकर्ता ने यह

रुख अपनाया कि एक बार कर चालान दाखिल करने के बाद इसे अधिनियम की धारा 8 (1) (क्रमशः अनुलग्नक पी4/ए और पी4/बी) के उद्देश्य से माल की बिक्री पर कर का भुगतान किए जाने का पर्याप्त प्रमाण माना जाना चाहिए। यह दावा किया जाता है कि चूंकि मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए सीमा 31.3.2007 पर समाप्त होने वाली थी, इसलिए, मूल्यांकन प्राधिकरण-प्रतिवादी संख्या 2 ने कोई और जांच किए बिना, पूर्व निर्धारित दिमाग के साथ याचिकाकर्ता का मूल्यांकन दिनांक 15.3.2007 (अनुलग्नक P5), आदेश के माध्यम से किया

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल)

785

और रु. 2,12,720-की मांग की गई है, जो तत्काल याचिका में चुनौती का विषय है।

(5) याचिकाकर्ता द्वारा नियमों के नियम 20 के साथ अधिकारातीत धारा 8 (3) को चुनौती दी गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार ये नियम सविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के खिलाफ है धारा 8 (3) के माध्यम से लगाई गई शर्तें मनमाना, अनुचित और कानून में टिकाऊ नहीं हैं।

(6) संयुक्त लिखित बयान में प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया। यह कहा गया था कि अधिनियम की धारा 8 (3) पूरी तरह से वैध है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं करती थी। यह विशेष रूप से अस्वीकार किया गया था कि उक्त प्रावधानों ने राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए कोई अत्यधिक शक्ति प्रदान की थी। इसमें आगे कहा गया है कि अधिनियम की उपरोक्त धारा 8 (3) और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 20 (1) और 20 (4) के प्रावधानों को याचिकाकर्ता द्वारा उसके लिए उपलब्ध वैधानिक उपचारों जो अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रदान किए गए मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील के उपचार को दरकिनार करने के लिए चुनौती दी है। यह भी कहा गया कि जहां एक कानून मूल्यांकन के आदेशों के खिलाफ उपचार प्रदान करता है, न्यायालय को ऐसे आदेशों के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने से बचना चाहिए।

(7) प्रतिवादी ने आगे प्रदर्शित किया कि अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) ने इनपुट कर के लिए एक निर्णायक साक्ष्य के रूप में प्रपत्र वैट सी-4 में प्रमाण पत्र की घोषणा नहीं की और उक्त प्रावधान, हालांकि, प्राधिकरण को केवल तभी दावे की अनुमति देने की अनुमति देता है जब प्राधिकरण जांच करने के बाद संतुष्ट हो कि प्रमाण पत्र में निहित विवरण सही और सही थे। यह भी उल्लेख किया गया है कि एक बार जब याचिकाकर्ता को इस तथ्य के बारे में पता चल जाता है कि राज्य को विक्रेताओं द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो याचिकाकर्ता अपने विक्रेताओं से कर की वापसी का दावा कर सकता है। जहां तक याचिकाकर्ता के इस कथन का संबंध है कि अधिनियम के तहत बनाई गई योजना ने न तो भारत के संविधान की धारा 19 (1) (जी) और न ही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है और याचिकाकर्ता का यह आरोप कि अधिनियम की धारा 8 (3) ने राज्य सरकार को नियम बनाने की अत्यधिक शक्ति प्रदान की है, गलत और गलत धारणा थी क्योंकि विधानमंडल ने अपने विवेक से अधिनियम की धारा 60 के तहत अधिनियम का उद्देश्य को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की थी। इसी तरह,

786

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(2)

अधिनियम की धारा 60 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियमों के नियम 20 के तहत प्रदत्त शक्ति भी अत्यधिक नहीं थी क्योंकि इसने इनपुट कर की गणना के लिए प्रक्रिया निर्धारित की थी जिसे विधायिका ने धारा 2 (डब्ल्यू) के तहत परिभाषित किया था और अधिनियम की धारा 3 (5) के तहत कटौती के लिए जो अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना का अभिन्न अंग था।

(8) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि नियमों के नियम 20 (1) और 20 (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 8 (3) मनमाना और असमान है। उन्होंने तर्क दिया कि क्रय व्यापारी से कर एकत्र करने वाला पंजीकृत विक्रय व्यापारी सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और इसलिए, इस तरह से

एकत्र कर जमा नहीं करने में पंजीकृत विक्रय व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी चूक के लिए क्रय व्यापारी पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की निगम बैंक बनाम सरस्वती आभारशाला और अन्य (1) मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया:—

“माल की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। इसे व्यापारी द्वारा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उस दर पर एकत्र किया जाना चाहिए जो निर्दिष्ट की जाए। न तो राज्य और न ही अभिकर्ता निर्दिष्ट दर से अधिक कर एकत्र करने के हकदार हैं।”

(10) माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम अतुल फास्टनर्स लिमिटेड (2) मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का भी समर्थन लिया :—

“ब्याज का भुगतान करने का सवाल भी नहीं उठेगा क्योंकि बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। यह निर्धारिती द्वारा अपने ग्राहकों से एकत्र किया जाता है। कर का प्रभाव निर्धारिती पर नहीं बल्कि उसके ग्राहकों पर पड़ता है। निर्धारिती बिक्री मूल्य के एक हिस्से के रूप में अपने ग्राहकों से बिक्री कर एकत्र करता है। यह निर्धारित अवधि के लिए उनके कारोबार का हिस्सा है। इस योजना के तहत निर्धारिती द्वारा कर का भुगतान करने की देयता हर साल उपार्जित होती है लेकिन कर का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है। सात वर्ष की समाप्ति पर निर्धारिती को 7 वर्षों के दौरान उसके द्वारा एकत्र किए गए कर का भुगतान करना होता है। यह एक प्रकार का ऋण है। जो

(1) 2009 (19) वीएसटी 84 (एससी)

(2) 2007 (4) एससीसी 471

राज्य द्वारा निर्धारिती को दिया जाता है ताकि निर्धारिती अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर राशि का उपयोग कर सके। जैसा कि कहा गया है कि प्रतिवादी निर्धारिती का दायित्व प्रत्येक वर्ष उपार्जित होता है, इसलिए विभाग द्वारा उस अवधि के दौरान निर्धारिती द्वारा एकत्र किए गए कर पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह कर निर्धारिती द्वारा अपने ग्राहकों से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एकत्र किया जाता था। निर्धारिती को उस राशि को अपने पास रखने की अनुमति है जो राज्य सरकार के खाते में जमा हुई है।”

(11) इसके बाद यह तर्क दिया गया कि विक्रेता द्वारा क्रय व्यापारी से प्राप्त इनपुट कर को जमा नहीं करने के कारण याचिकाकर्ता पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि "भुगतान" शब्द की व्याख्या "भुगतान किया जाना चाहिए" के अर्थ में की जानी चाहिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने संजना, सहायक कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे और अन्य बनाम द एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड (3), में अभिनिर्धारित किया गया था जो निम्नलिखित है:-

“यह अब हमें नियम 10 में "अल्पकालिक" और "भुगतान" अभिव्यक्ति पर रखी जाने वाली उचित व्याख्या के प्रश्न पर ले जाता है। क्या "अल्प-शुल्क" अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि कुछ राशि शुल्क के रूप में लगाई जानी चाहिए थी जैसा कि डॉक्टर शैयद मोहम्मद द्वारा तर्क दिया गया है या क्या यह अभिव्यक्ति उन मामलों को भी शामिल करेगी जहां मूल्यांकन शून्य शुल्क का है, जैसा कि Mr. Daphtary द्वारा तर्क दिया गया है? नियम 10 में "भुगतान" शब्द का क्या अर्थ है? अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि इसका अर्थ है "वास्तव में भुगतान किया गया", जबकि प्रतिवादी के अनुसार इसका अर्थ है "भुगतान किया जाना चाहिए था"। शाब्दिक रूप से "भुगतान" शब्द का अर्थ वास्तव में नकद में भुगतान करना है। इसका मतलब है कि किसी

पक्ष या निर्धारिती ने शुल्क की कुछ राशि जो किसी भी मात्रा में हो सकती है का भुगतान किया होगा। यदि इस शाब्दिक व्याख्या को नियम 10 में "भुगतान" अभिव्यक्ति पर रखा जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह बड़े पैमाने पर डॉक्टर शैयद मोहम्मद के इस तर्क का समर्थन करेगा कि नियम 10 इस अर्थ में एक अल्प-शुल्क पर विचार करता है कि जो राशि सही राशि से कम है, उसका आकलन किया गया है और वास्तव में भुगतान किया गया है। हमारी राय में, "भुगतान" अभिव्यक्ति को शून्य में नहीं पढ़ा जाना चाहिए और उक्त शब्द का अर्थ शाब्दिक रूप से लगाना सही नहीं होगा।

(3) एयर 1971 एससी 2039

788

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(2)

जिसका अर्थ है वास्तव में भुगतान किया गया। उस शब्द को उस संदर्भ में समझना और व्याख्या करनी होगी जिसमें उसके उचित अर्थ की खोज होती हो यदि इसकी संदर्भ में इसके गुण जानने पर विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि "भुगतान" शब्द के अर्थ में अस्पष्टता है। यह याद रखना चाहिए कि नियम 10 शुल्कों या कम लगाए गए या गलती से वापस किए गए शुल्कों की वसूली से संबंधित है। "भुगतान" अभिव्यक्ति का उपयोग लिखित मांग जारी करने के लिए तीन महीने की सीमा के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाने के लिए किया गया है। अधिनियम और नियम बहुत विस्तार से बताते हैं कि किस स्तर पर और किस समय किसी पक्ष द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना है। यदि वास्तविक रूप से यह माना जाता है कि राशि का वास्तव में भुगतान किया जाना चाहिए था, तो वर्तमान की तरह, जब कोई शुल्क नहीं लगाया गया है, तो विभाग नियम 10 के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। नियम 10-ए तब लागू नहीं हो सकता जब किसी अधिकारी की ओर से त्रुटि या गलत निर्माण द्वारा से एक लघु-शुल्क लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा मामला विशेष रूप से नियम 10 द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए, हमारी राय में, "भुगतान" अभिव्यक्ति पर रखी

जाने वाली उचित व्याख्या "भुगतान किया जाना चाहिए था"। इस तरह की व्याख्या कुछ अन्य अधिनियमों में होने वाली "भुगतान" अभिव्यक्ति पर रखी गई है जैसे कि गुरसाई सहगल बनाम इनकमटैक्स के आयुक्त, पंजाब (1963) 3 एससीआर 893 = (एआईआर 1963 एससी 1062) और एलन बनाम थोर्न इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1968) 1 क्यू बी 487 में।"

(12) विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) और (4) और प्रपत्र वैट सी-4 मनमाने ढंग से निर्धारित कर रहे हैं, जिसके तहत क्रय व्यापारी को यह स्थापित करने की आवश्यकता होती है कि इसकी सामग्री सही है। इसका अर्थ यह है कि निर्धारिती के लिए यह स्थापित करना कि पंजीकृत विक्रय व्यापारी ने क्रय व्यापारी से एकत्र कर जमा किया है, एक कठिन शर्त है जो पूरा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि क्रय व्यापारी का पंजीकृत विक्रय व्यापारी या उसके पूर्ववर्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बाद यह आग्रह किया गया कि राज्य के पास वास्तविक चूककर्ता से वसूली करने के लिए सभी तंत्र हैं और चूक करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य निकाय की चूक के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न न्यायालयों के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थी।

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल)

789

मेसर्स चुनी लाल पारशदी लाल बनाम बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ (4), विकास पाइप बनाम आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क सी. एक्स. के। चंडीगढ़-॥ (5), गोविंदन एंड कंपनी बनाम तमिलनाडु राज्य (6), बहु धातु उत्पाद बनाम बिक्री कर आयुक्त, एम. पी. (7)।

(13) विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राज्य को उस स्थिति में क्रय व्यापारी से वसूली लागू करने का हकदार ठहराया जा सकता है जब लेन-देन धोखाधड़ी से प्रेरित होता है या क्रय व्यापारी और पंजीकृत विक्रय व्यापारी के बीच कोई मिलीभगत स्थापित होती है।

(14) निर्धारिती के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए, यह आग्रह किया गया कि अधिनियम और नियमों के प्रावधान कानूनी हैं और राज्य को इसके कारण होने वाले वैध राजस्व की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत, राज्य क्रय व्यापारी से कर एकत्र करने के लिए अधिकृत है, जहां यह पाया जाता है कि पंजीकृत विक्रय व्यापारी द्वारा दी गई घोषणा गलत है। इन सिद्धांतों के प्रावधान को अधिकारातीत और कानून में खराब घोषित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, लिखित बयान में लिए गए रुख को दोहराया गया।

(15) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कीये गए संबंधित तर्कों पर काफी विचार विमर्श किया।

(16) अधिनियम की योजना में यह परिकल्पना की गई है कि जो कोई भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे धारा 11 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और पूरी मूल्यांकन प्राधिकरण पूरी तरह संतुष्ट है कि आवेदक एक वास्तविक विक्रेता था और उस उद्देश्य के लिए प्रतिभूति देने के लिए आवेदन धारा 12 के प्रावधानों के अधीन था। जब कोई व्यापारी जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, तो मूल्यांकन प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जांच करने और कर जमा करने और प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए एक शर्त के रूप में लिखित रूप में निर्देश देने के लिए बाध्य होता है। यह पंजीकरण प्रमाणपत्र की मुद्रा के दौरान भी किया जा सकता है यदि देय कर की उचित प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा गया था। यह अधिनियम कर की उचित जमा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से पहले से दी गई प्रतिभूति पर्याप्त नहीं होने की स्थिति में विक्रेता को अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करने का निर्देश देने के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण को अधिकार देता है। एक बार इन सब

(4) ए. आई. आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट 1966

(5) 2003 (158) ई. एल. टी. 680 (पी एंड एच)

(6) 1975 (35) एस. टी. सी. 50 (मद्रास)

(7) 1999 (112) एस. टी. सी. 605 (एम. पी.)

आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा होने पर, आवेदक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो खरीदारों से कर संग्रह के लिए भी अधिकृत होता है। अधिनियम का अध्याय VIII विभिन्न घटनाओं में अपराधों और दंड से संबंधित है। हालाँकि, यदि वह व्यक्ति जो खुद को पंजीकृत नहीं करता है या कर एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं है और फिर भी कर एकत्र करता है, तो वह अधिनियम की धारा 39 के तहत प्रदान किए गए दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(17) पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र रखने वाले व्यापारी जो कर एकत्र करने के लिए अधिकृत है, उसे अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करना होगा। वह अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में समय-समय पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य है। उसे मामले के अनुसार धारा 14 (3) या 14 (4) के संदर्भ में कर का भुगतान करने की भी आवश्यकता होती है, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह अधिनियम की धारा 14 (6) के तहत दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। रिटर्न के साथ, व्यापारी को मूल्यांकन प्राधिकरण को क्रमशः एल. पी.-7 और एल. एस.-9 प्रपत्रों में खरीद और बिक्री की एक सूची प्रस्तुत करनी होती है।

(18) अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) और नियम 20 के उप-नियम (1) और (4) को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

धारा 8.(निवेश कर का निर्धारण)

(1)

(2)

(3) जहां इस अधिनियम के तहत किसी व्यापारी को बेचे गए किसी माल के संबंध में इनपुट कर पर सवाल उठाया जाता है, तो ऐसी कार्यवाही करने वाला प्राधिकरण ऐसे व्यापारी से माल की बिक्री के संबंध में विक्रेता द्वारा उसे जारी किए गए कर चालान के अलावा, विक्रेता द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से उसे प्रस्तुत एक प्रमाण पत्र पेश करने की माँग कर सकता है और ऐसा प्राधिकरण दावे की

अनुमति केवल तभी देगा जब वह ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे करने के बाद संतुष्ट हो जाए कि उसके सामने पेश किए गए प्रमाण पत्र में निहित विवरण सही और सच हैं।”

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल)

791

नियम 20 [एक विक्रेता वैट व्यापारी द्वारा प्रमाण पत्र का प्रपत्र।धारा 8 (3)]:

- (1) धारा 8 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र वैट-सी4 प्रपत्र में होगा और बिक्री वैट विक्रेता द्वारा क्रय कर व्यापारी को उसके द्वारा कर चालान पर की गई कर योग्य वस्तुओं की बिक्री के संबंध में क्रय वैट व्यापारी को तब प्रस्तुत किया जाएगा जब ऐसी बिक्री पर अधिनियम के तहत देय कर का उसके द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया हो।
- (2) XXXXXXXX
- (3) XXXXXXXX
- (4) कर चालान पर अन्य वैट व्यापारी को उसके द्वारा माल की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए एक विक्रेता वैट व्यापारी की देनदारी उपशमन करना नहीं होगी यदि वह क्रय करने वाले वैट व्यापारी को पूर्वगामी उप-नियम में निर्दिष्ट गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है या गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है और इस कारण से कर बाद वाले से वसूल किया गया है, लेकिन यदि विक्रेता वैट व्यापारी बाद में उससे देय कर का भुगतान करता है, तो खरीद करने वाले वैट व्यापारी की देनदारी तदनुसार उपशमन हो जाएगी और वह अपने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के तीन साल के भीतर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है।”

उपरोक्त नियम प्रपत्र वैट सी-4 निर्धारित करता है, एक घोषणा जिसे अधिनियम के तहत विवरणी दाखिल करते समय क्रय व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। संशोधित वैट सी-4 प्रपत्र का प्रारूप इस प्रकार है:

{(नियम 20 (1), (2) और (3) देखें)}।

प्रमाणपत्र

धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत निवेश कर के दावे के लिए कर योग्य वस्तुओं के संबंध में एक विक्रेता वैट डीलर द्वारा एक खरीदार वैट डीलर को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र। प्रमाणित किया कि मैं/हम।.....
(विक्रेता का नाम और पूरा पता) जिसके पास

792`

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2012(2)

कर दाता पहचान संख्या (टी. आई. एन.).....
जिले में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत पंजीकृत;(i) टी. आर. No.....date..... के माध्यम से हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत कर की पूरी राशि का भुगतान किया है।/(ii) टी. आई. एन..... रखने वाले मेसर्स(क्रय व्यापारी का नाम और पूरा पता) को बेचे गए माल पर टी. आई. एन..... रखने वाले मेसर्स(बिक्री व्यापारी का नाम और पूरा पता) को भुगतान किए गए इनपुट कर को समायोजित किया है।-

सं.	बेचे गए माल का विवरण	कर चालान सं।	तिथि	कर योग्य राशि	कर की राशि

कुल

1. कुल कर योग्य राशि: रु.....

2 कर की कुल राशि: रु.....

स्थान.....।

तारीख:.....

बेचने वाले वैट व्यापारी के हस्ताक्षर।

नाम.....

स्थिति.....

व्यापारी की मुहर

(आधिकारिक की मुहर)

- *ध्यान दें: 1. मूल प्रति जो विक्रेता द्वारा क्रय विक्रेता को जारी की जानी है।
2. बेचने वाले वैट विक्रेता द्वारा डुप्लिकेट प्रति रखी जानी चाहिए।
3. जो भी लागू न हो, हटा दे।”

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल)

793

(19) विश्लेषण करने पर, याचिका में विवाद इस बात तक सीमित हो जाता है कि क्या एक क्रय व्यापारी को इनपुट कर के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो पंजीकृत विक्रय व्यापारी या उसके पूर्ववर्तियों द्वारा उससे वसूल किया गया है लेकिन सरकारी खजाने में भुगतान नहीं किया गया है।

(20) एक वैट व्यापारी और कर योग्य कारोबार को अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (डब्ल्यू) इनपुट कर को परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 60 राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 8 के तहत निवेश कर के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के सादे तौर पर पढ़ने से ज्ञात होता है कि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में जहां भी किसी व्यापारी को माल की बिक्री के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे की जांच की जानी है, वहां कार्यवाही करने वाले प्राधिकरण विक्रेता से माल की बिक्री के संबंध में विक्रेता द्वारा उसे जारी

किए गए कर चालान और विक्रेता से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग करने में सक्षम है। क्रय व्यापारी उक्त प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता और सच्चाई के संबंध में मूल्यांकन प्राधिकरण को संतुष्ट करने पर दावे के लिए क्रेडिट का हकदार होगा।

(21) नियम 20 के उप नियम (1) में कहा गया है कि वैट अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत निर्धारित प्रमाण पत्र फॉर्म वैट सी-4 में होगा, जिसे विक्रेता द्वारा खरीद व्यापारी को कर योग्य वस्तुओं की बिक्री से संबंधित खरीद वैट व्यापारी को प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि अधिनियम के तहत देय कर का उसके द्वारा पूरा भुगतान किया गया हो।

(22) नियम 20 के उप नियम (4) में कहा गया है कि खरीददार वैट व्यापारी को वैट सी-4 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता या गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में उसको दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, जहां भी विक्रेता बाद में उससे देय कर का भुगतान करता है, उस स्थिति में क्रय व्यापारी की देनदारी समाप्त हो जाएगी। यह क्रय व्यापारी को अपने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के तीन साल के भीतर उससे एकत्र किए गए कर की वापसी की मांग करने का अधिकार देगा।

(23) असंवैधानिकता की घोषणा से बचने के लिए, न्यायालयो ने व्याख्या के ऐसे सिद्धांतों को अपनाया है जो कानून को बनाए रखे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मेसर्स छोटाभाई जेठाभाई पटेल एंड कंपनी** और अन्य (8), पैरा 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

“यह तय किया गया कानून है कि जहां एक विधायी प्रावधान के दो निर्माण संभव हैं, तो वह जो संविधान की संवैधानिकता के अनुरूप है और दूसरा उसके विरोध में है तो न्यायालय उसको अधिमान देगा जो आक्षेपित अधिनियम

के उद्देश्य और प्रयोजन के साथ संगत है, और जिसने प्रासंगिक कारकों से इसके वास्तविक दायरे और अर्थ का पता न लगाने वाली शरारत रोकने की कोशिश की थी को अधिमान देगा।”

(24) इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य (9), पैरा 38 में निम्नलिखित कहा था: “विधायिका के प्रति संवैधानिक सम्मान और लोकतांत्रिक धारणा है कि जन प्रतिनिधि समुदाय के विवेक को व्यक्त करते हैं, जो अदालतों को कानूनों की व्याख्या में ले जाता है जो प्रावधान की वैधता को संरक्षित और बनाए रखता है। कहने का मतलब है, अदालतों को बुद्धिमान कल्पना के साथ, संविधान के मूल्यों के बारे में खुद को सूचित करना चाहिए और कार्यात्मक लचीलेपन के साथ, उस निर्माण को अपनाने के लिए अर्थों के अर्थ का पता लगाना चाहिए जो मानवीय रूप से विचाराधीन अधिनियम को संवैधानिक बनाता है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें कारागार अधिनियम के नियम 30 और 56 और कारागार नियमावली के पैराग्राफ में शब्दों की व्याख्या इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि शब्द पुराने क्रम के हों, लेकिन अर्थ नए क्रम को प्रसारित करता है। वेम्स बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (1909) 54 एल एड 793 पेज 801 में चमकदार दिशानिर्देश हमारी नज़रों को ऊंचा रखता है:

“कानून, वैधानिक और संवैधानिक दोनों, अधिनियमित किया जाता है, यह बुराई के अनुभव से सच है, लेकिन-इसलिए, इसकी सामान्य भाषा को आवश्यक रूप से उस रूप तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए जो बुराई ने लिया था। समय कार्य बदलता है, नई स्थितियों और उद्देश्यों को अस्तित्व में लाता है। इसलिए, एक सिद्धांत, महत्वपूर्ण होने के लिए, उस शरारत की तुलना में व्यापक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए जिसने इसे जन्म दिया। यह संविधानों के बारे में विशेष रूप से सच है। वे अल्पकालिक अधिनियम नहीं हैं, जो बीतते अवसरों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। वे, मुख्य न्यायाधीश मार्शल के शब्दों में, “अमरता तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जितना कि

मानव संस्थान इसे प्राप्त कर सकते हैं।" भविष्य उनकी देखभाल और घटनाओं के लिए प्रावधान है।

(9) ए. आई. आर 1978 एस. सी. 1675

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (न्यायमूर्ति अजय कुमार मिश्र)

795

जिनकी अच्छी और बुरी प्रवृत्तियाँ की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसलिए, एक संविधान को लागू करने में, हमारा चिंतन केवल जो हुआ है, उसके बारे में नहीं हो सकता है, बल्कि जो हो सकता है उसके बारे में हो सकता है। किसी भी अन्य नियम के तहत एक संविधान को लागू करना वास्तव में उतना ही आसान होगा जितना कि यह होगा। किसी भी अन्य नियम के तहत एक संविधान को लागू करना वास्तव में उतना ही आसान होगा जितना कि इसकी प्रभावकारिता और शक्ति में कमी होगी। इसके सामान्य सिद्धांतों का बहुत कम मूल्य होगा, और इसे पूर्ववर्ती रूप से नपुंसक और निर्जीव सूत्रों में परिवर्तित किया जाएगा। शब्दों में घोषित अधिकार वास्तविकता में खो सकते हैं। और इस बात को स्वीकार किया गया है। संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक निर्माण के खिलाफ संविधान का अर्थ और जीवन शक्ति विकसित हुई है।"

(25) कानूनी न्यायशास्त्र में, दायित्व उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जो या तो धोखाधड़ी से कार्य करता है या अपराधी के साथ मिलीभगत या मिलीभगत का एक पक्ष रहा है। हालांकि, कानून में कहीं भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जुर्माना लगाने की परिकल्पना नहीं की गई है, जहां कोई व्यक्ति ऐसी किसी घटना या कार्य से जुड़ा नहीं है। कानून एक लगभग असंभव घटना की परिकल्पना नहीं कर सकता है। निर्धारिती की जिम्मेदारी वैट सी-4 प्रपत्र को प्रस्तुत करने पर समाप्त हो जाती है जो वास्तविक होना आवश्यक है और उसके बाद इसकी प्रामाणिकता के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़कर इसकी सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए नहीं। निर्धारिती के किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे,

मिलीभगत या विक्रेता व्यापारी या किसी भी व्यापारी के साथ गलत जुड़ाव की अनुपस्थिति में, प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। कानून निर्धारिती पर ऐसी भारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता है अन्यथा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 की कसौटी पर कानून को वैध ठहराना मुश्किल होगा।

(26) व्याख्या के नियम की आवश्यकता है कि ऐसा अर्थ उस प्रावधान को दिया जाना चाहिए जो अधिनियम के प्रावधान को प्रभावी बनाएगा और अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा। यह जहां भी संभव हो, प्रावधान की भाषा के साथ कोई हिंसा किए बिना किया जाना चाहिए। अधिनियम को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि पक्षकारों के साथ न्याय हो सके। यदि यह माना जाता है कि जो व्यक्ति कर जमा नहीं करता है या उसे कर जमा करने की आवश्यकता है, तो उसे एक लाभप्रद स्थिति में रखा जाएगा और जबकि कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति बदतर होगा, तो ऐसी व्याख्या एक अर्थहीनता होगी। इस तरह कि व्याख्या से बचना चाहिए।

(27) दूसरे शब्दों में, प्रमाण पत्र और घोषणा की वास्तविकता की जांच प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है, लेकिन उसमें दर्ज किए गए बयानों की शुद्धता या सच्चाई स्थापित करने की जिम्मेदारी निर्धारिती पर नहीं डाली जा सकती है। अधिकारी इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या वैट सी-4 फॉर्म फर्जी था और व्यापारी द्वारा विक्रेता के साथ मिलीभगत में खरीदा गया था। उचित घोषणा प्रस्तुत किए जाने के बाद विभाग को दावे की अनुमति देने की आवश्यकता होती है और इसके गलत होने की स्थिति में, जब घोषणा की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया हो विभाग चूककर्ता के खिलाफ आगे बढ़ सकता है। हालांकि, उस स्थिति में एक अपवाद बनाया गया है जब पंजीकृत खरीद व्यापारी या तत्काल पूर्ववर्ती पंजीकृत विक्रेता या पंजीकृत व्यापारी को पूर्ववर्तियों में से किसी के बीच धोखाधड़ी, मिलीभगत या मिलीभगत स्थापित हो जाती है, तो फॉर्म वैट सी-4 में निहित लाभ पंजीकृत खरीद व्यापारी को उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त व्याख्या के

परिणामस्वरूप नियम का उद्देश्य प्राप्त होगा जो अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य को व्यवहार्य बनाना है, यानी वैध तरीकों से राजस्व कर की प्राप्ति।

(28) मेसर्स चुन्नी लाल पारशदी लाल के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों पर विचार करते हुए जहां विक्रेता पर कर की देनदारी निर्धारित करने की मांग की गई थी, जिसमें विक्रेता से यह साबित करने की आवश्यकता थी कि खरीद के बाद खरीद व्यापारी ने माल के साथ कैसे व्यवहार किया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ ऐसी बिक्री पर कर के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है:

“लेकिन डीलर के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान मामले में अधिनियम के प्रावधानों को लागू और प्रभावी, करने बारे था जबकि नियमों में ऐसा नहीं है इसलिए यह एक अकाट्य अनुमान को उठती है। हमारी राय है कि इस निवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए। आखिरकार, इस नियम का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य को व्यवहार्य बनाना था, यानी उपभोक्ता को एक ही बिंदु यानी बिक्री के बिंदु पर कर की प्राप्ति। नियम के प्रावधानों को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि नियम के उद्देश्य को पूरा करने में सुविधा हो।

एक ऐसी व्याख्या जो अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाएगी और अधिनियम के उद्देश्य को लागू करेगी, भाषा के साथ हिंसा किए बिना जब भी संभव हो, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रमाण पत्र और घोषणा की वास्तविकता की जांच कर प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है, लेकिन ब्यान की शुद्धता या सच्चाई की नहीं।

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल)

797

बिक्री कर अधिकारी इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या प्रमाण पत्र "फरज़ी" है या नहीं, या क्या विक्रेता व्यापारी की कोई मिलीभगत थी, लेकिन उससे आगे नहीं-यानी खरीद व्यापारी ने माल के साथ कैसे व्यवहार किया

है। यदि किसी उपयुक्त मामले में यह स्थापित किया जा सकता है कि प्रमाण पत्र "फरज़ी" थे या कि खरीद व्यापारी और बेचने वाले व्यापारी के बीच मिलीभगत थी, तो अलग-अलग विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन इस मामले के तथ्यों में, जैसा कि पहले देखा गया है, तथ्यों को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इसके विपरीत पाया गया है, हालांकि यह बिक्री कर अधिकारी का निष्कर्ष था। उस उद्देश्य के लिए प्रश्न को टाल दिया गया है अर्थात् इस मामले में पाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में वास्तविक विवाद को लाने के लिए।"

(29) गोविंदन एंड कंपनी के मामले (उपरोक्त) में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक व्यापारी के दायित्व से संबंधित मामले में, जहां कर के लाभ का दावा इस आधार पर किया गया था कि निर्धारिती द्वारा की गई बिक्री दूसरी बिक्री थी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं थी कि उनके विक्रेताओं ने वास्तव में कर का भुगतान किया था। उनके लिए यह दिखाने की आवश्यकता थी कि पहले की बिक्री कर योग्य बिक्री थी और कर वास्तव में उनके विक्रेताओं द्वारा देय था। निष्कर्ष इस प्रकार है:

"यद्यपि न्यायाधिकरण का आदेश अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा पारित प्रेषण आदेश को बरकरार रखने वाला है, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायाधिकरण का यह निर्देश कि याचिकाकर्ताओं को यह साबित करना है कि जिन बारह विक्रेताओं से उन्होंने सामान खरीदा था, वे वास्तविक व्यक्ति थे और उन्होंने वास्तव में लोहे और इस्पात पर कर का भुगतान किया था, सही नहीं है और यह याचिकाकर्ताओं का कर्तव्य नहीं है कि वे यह साबित करें कि उनके विक्रेताओं ने वास्तव में उनकी बिक्री पर कर का भुगतान किया है। विद्वान अधिवक्ता अपनी दलील में सही प्रतीत होता है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर कर से छूट का दावा किया है कि उनकी बिक्री दूसरी बिक्री है, वे यह दिखाने के लिए बाध्य हैं कि पूर्ववर्ती कर योग्य बिक्री हुई है और उन्हें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में उन पूर्ववर्ती बिक्री पर कर का भुगतान किया गया था। इस आधार पर कर के लाभ का दावा करने के लिए कि उनकी बिक्री दूसरी बिक्री है, याचिकाकर्ताओं को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उनके विक्रेताओं ने

वास्तव में कर का भुगतान किया है और यह उनके लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पहले की बिक्री कर योग्य बिक्री है और कर वास्तव में उनके विक्रेताओं द्वारा देय है।

इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्देश कि याचिकाकर्ताओं को यह दिखाना है कि उनके विक्रेताओं द्वारा याचिकाकर्ताओं को बेचे गए लोहे और इस्पात के सामान पर कर का भुगतान किया गया है, सही नहीं प्रतीत होता है।”

(30) इस फैसले के खिलाफ दायर सिविल अपील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम रमन एंड कंपनी और अन्य (10) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में पारित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

(31) उपरोक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बहु धातु उत्पादों के मामले (उपरोक्त) में निम्नलिखित शब्दों में इसी तरह का विचार लिया गया था:

“इसलिए, एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि कच्चा माल या आनुषंगिक सामान एक पंजीकृत विक्रेता से खरीदा गया है जो दर्शाता है कि माल कर-भुगतान किया गया है और यदि माल पर कर नहीं लगाया गया है, तो मूल्यांकन प्राधिकरण के लिए पंजीकृत विक्रेता से पूछ सकता है। धारा 8 को प्रभावी बनाने के लिए नियम 20-सी बनाया गया है। धारा (iv) में यह प्रावधान है कि भुगतान का दावा करने वाला विक्रेता, मूल्यांकन के समय, इस तथ्य के समर्थन में कि उसके द्वारा खरीदे गए कच्चे माल या आनुषंगिक वस्तुओं पर बिक्री पंजीकृत विक्रेता के हाथों धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत पूरी दर से कर लगाया गया है। इसलिए, नियम 20-सी के धारा (iv) के आधार पर, एक बार जब क्रय व्यापारी पंजीकृत व्यापारी का बिल पेश कर देता है तो यह माना जाएगा कि माल पर कर का बोझ पड़ा है। यदि इसके बारे में कोई संदेह है तो निर्धारिती को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बजाय, वह इसके लिए सबूत एकत्र करता है। किसी भी संदेह की स्थिति में मूल्यांकन प्राधिकरण को यह पता लगाना चाहिए कि माल पर कर लगाया गया है या

नहीं। एक बार जब कानून पंजीकृत व्यापारी और कर-भुगतान माल को परिभाषित कर देता है, तो निर्धारिती, यानी खरीद व्यापारी, पंजीकृत व्यापारी द्वारा जारी किए गए बिल को पेश करता है, फिर उसका बोझ हटा दिया जाता है और उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है या उसे छूट प्राप्त आदेश के लिए सामग्री एकत्र आदेश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बल्कि, यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो आवश्यक विवरण प्राप्त करना मूल्यांकन प्राधिकरण पर होना चाहिए।

(10) 1994 (93) एसटीसी 185

मेसर्स घेरू लाल बाल चंद बनाम हरियाणा राज्य
और अन्य (न्यामूर्ति अजय कुमार मित्तल)

799

गोविंदन एंड कंपनी बनाम तमिलनाडु राज्य (1975) 35 एसटीसी 50 में सवाल यह था कि क्या माल पर एकल बिंदु कर लगाया जाता है या नहीं और उस संदर्भ में, यह देखा गया:

“इस आधार पर कर के लाभ का दावा करने के लिए कि निर्धारिती द्वारा की गई बिक्री दूसरी बिक्री है, निर्धारिती को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उनके विक्रेताओं ने वास्तव में कर का भुगतान किया है। उनके लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पहले की बिक्री कर योग्य बिक्री है और कर वास्तव में उनके विक्रेताओं द्वारा देय है।”

(32) इसके अलावा, क्रेता-पंजीकृत व्यापारी जिसने कर खरीद-पंजीकृत व्यापारी से एकत्र किया था, वह सरकार के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसा कि अतुल फास्टनर्स लिमिटेड के मामले (ऊपर) में हुआ था। और भी आगे, भुगतान किया जाएगा मतलब और इसके भीतर आलिंगन का भुगतान किया जाना चाहिए था जैसा कि एल्फिंस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड का मामला (ऊपर) में कहा गया है। इसके अलावा, बी. आर. एंटरप्राइजेज बनाम यू. पी. राज्य (11), कलकत्ता गुजराती एजुकेशन सोसाइटी बनाम कलकत्ता नगर निगम (12)

और एम. नागराज बनाम भारत संघ (13) में शीर्ष अदालत ने व्याख्या की है। सांविधिक प्रावधानों को पढ़ने के नियम का अर्थ यह है कि एक सांविधिक प्रावधान को आम तौर पर पढ़ा जाता है ताकि प्रावधान को असंवैधानिक या अधिकारातीत घोषित होने से बचाया जा सके। नियम को प्रावधान पढ़ने का मतलब प्रावधान को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझना और एक अधिनियम को व्यवहार्य बनाने के लिए कड़वाहट को सीधा करना या दरारों को इस्ती करना है।

(33) निष्कर्ष है कि, ट्रेजरी में बिक्री पंजीकृत डीलर द्वारा कर का भुगतान न करने के कारण खरीद पंजीकृत डीलर पर कोई देयता नहीं लगाई जा सकती है, जब तक कि यह धोखाधड़ी न हो, या पंजीकृत बिक्री डीलर या उसके पूर्ववर्तियों के साथ खरीद पंजीकृत डीलर के साथ मिलीभगत या मिलीभगत स्थापित न हो जाए।

(34) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि अधिनियम की धारा 8 (3) के प्रावधान और नियम 20 के उप-नियम (1) और (4) अधिकारातीत हैं, लेकिन वे ऊपर बताए गए तरीके से लागू होंगे। नतीजतन, रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और मूल्यांकन आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और मामलों को कानून के अनुसार नए मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए मूल्यांकन प्राधिकरण को भेज दिया जाता है।

(11) 1999 (9) एससीसी 700

(12) 2003 (10) एससीसी 533

(13) 2006 (8) एससीसी 212

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)